

बलवीर सिंह और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 253 / 2016)

10 मई, 2016

[ए. के. सिकरी और आर. के. अग्रवाल, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 190 और 193-मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध के संज्ञान के बाद सत्र न्यायालय को मामले का कमित करना -क्या सत्र न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है जब इसी तरह का आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय खारिज कर दिया गया किया गया था। अभिनिर्धारित किया गया: जब मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को कमित किया जाता है, धारा 193 के अंतर्गत, तब सत्र न्यायालय 'मूल अधिकारिता के न्यायालय' के रूप में यह पहली बार संज्ञान लेगा और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय पारित कोई भी आदेश उस अपराध का संज्ञान लेने के बराबर नहीं होगा जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है-क्योंकि सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है, अंतर्गत धारा 193, मजिस्ट्रेट मामले में संज्ञान लेने और समन जारी करने के लिए सशक्त है , और इसे उसी अपराध का दूसरा संज्ञान लेने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :- 1. धारा 190 किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, और द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट जो उसमें उल्लिखित तीन

परिस्थितियों के तहत "किसी भी अपराध" का संज्ञान लेने के लिए विशेष रूप से सशक्त हैं। इन तीन परिस्थितियों में पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे तथ्यों का संज्ञान लेना शामिल है जो अपराध बन सकते हैं। यह साधारण कानून है कि जब पुलिस रिपोर्ट यह कहते हुए दर्ज की जाती है कि कोई अपराध नहीं हुआ है, तो मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को नजरअंदाज कर सकता है और जांच से उभरे तथ्यों को स्वतंत्र रूप से लागू करने और उसका संज्ञान लेने में सक्षम है, यदि उसे लगता है कि जांच से सामने आने वाले तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि अपराध कारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (ए) के तहत मामले का संज्ञान लेने के लिए संहिता की धारा 200 और 202 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि उसके लिए धारा 200 या धारा 202 के तहत भी कार्य करने का विकल्प खुला है। इस प्रकार, जब शिकायत प्राप्त होती है अधिनियम की धारा 190 (1) (ए) के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 200 में निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेने का अधिकार है या 202 संहिता का पालन करें और फिर संज्ञान लें। यदि पुलिस रिपोर्ट दायर की जाती है, तो वह संहिता की धारा 190 (1) (बी) के तहत प्रदान की गई ऐसी रिपोर्ट पर संज्ञान लेगा। इसी तरह, संहिता की धारा 193 सत्र न्यायालय को इसका संज्ञान लेने का अधिकार देती है। और कहती है कि सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि इस संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सौंप नहीं दिया गया हो। इस धारा के अनुसार, सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे जाने के बाद ही संज्ञान ले सकता है। हालांकि, एक बार जब मामला मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए कमिट हो जाता है, तो सत्र न्यायालय को 'मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय' के रूप में कार्य करते हुए संज्ञान लेने का अधिकार होता है। उक्त उपबंध को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकता है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है या उसे मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने के बाद मामले

को सत्र न्यायालय को सौंपना होगा क्योंकि सत्र न्यायालय ही ऐसे मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है। एक ओर, संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेट को "किसी भी अपराध का संज्ञान लेने" का अधिकार देती है, जिससे यह आभास होता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का भी संज्ञान ले सकता है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दूसरी ओर, जब मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है, तो संहिता की धारा 193 यह निर्धारित करती है कि सत्र न्यायालय 'मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में' संज्ञान लेगा, जो दर्शाता है कि संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया है। सत्र न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के रूप में और, इस प्रकार, यह पहली बार है कि संज्ञान लिया गया है और मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कोई भी आदेश उस अपराध का संज्ञान लेने के समान नहीं है जो विचारणीय है। सत्र न्यायालय. संहिता की धारा 190 को पढ़ने से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि मजिस्ट्रेट केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध के लिए ही संज्ञान ले सकता है, उसके संबंध में नहीं जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हैं। इस प्रकार, उसके पास शक्ति है किसी ऐसे अपराध का संज्ञान लेने की जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। यदि ऐसा है, तो सवाल यह है कि जब सत्र न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो संहिता की धारा 193 में आने वाले "मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में" शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाए। इसे अन्यथा कहें तो, जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है और उसके बाद मामले को केवल सत्र न्यायालय को सौंप दिया है, तो क्या सत्र न्यायालय को संहिता की धारा 193 के तहत किसी अपराध का फिर से संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है या उसके पास अभी भी मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए संज्ञान लेने की शक्ति है।

2. यह एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की गई थी, आई. ओ. ने अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में अपीलार्थी को इसमें शामिल नहीं किया

था। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भी संज्ञान लेने के अनुरोध के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया था । इस आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। इस स्थिति में इस प्रकार, मामला वह नहीं है जहां संहिता की धारा 173(8) के तहत अपीलार्थियों को फंसाया गया, जांच रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल किया गया है और अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है । इसके विपरीत, पुलिस ने स्वयं अपनी अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि अपीलार्थियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई, जो चाहता था कि मजिस्ट्रेट इन अपीलार्थियों को भी समन करे और इस उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता द्वारा संहिता की धारा 190 के तहत आवेदन दायर किया गया था। अपीलार्थियों ने उक्त आवेदन का उत्तर दिया था और दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट का आदेश उचित बुद्धि का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था जिसमें उन्होंने अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया और इसे केवल अपीलार्थियों के बेटे तक ही सीमित रखा। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई। आम तौर पर, ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि जी मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय में सौंपते समय 'निष्क्रिय भूमिका' निभाई थी। इस प्रकार, उन्होंने उचित दिमाग लगाने और इस प्रक्रिया में "सक्रिय भूमिका" निभाने के बाद संज्ञान लिया था। स्थिति अलग होती यदि मजिस्ट्रेट ने मामले को कमिट करते समय शिकायतकर्ता के आवेदन को सत्र न्यायालय में भेज दिया होता। इस परिदृश्य में, यह ऐसा मामला होगा जिसमें मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है। इसके बावजूद, सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा अपने समक्ष किए गए इसी तरह के आवेदन पर संज्ञान लिया। आम तौर पर, इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है।

3. . अगला सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय ऐसे आदेश पर रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता के आवेदन पर जवाब दाखिल करने वाले अपीलार्थीओं को उचित अवसर दिया गया था और सत्र न्यायालय ने उनकी दलीलें भी सुनी थीं। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

धरम पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (2014) 3 एससीसी 306 - अनुसरण किया गया।

निसार एवं अन्य बनाम यू.पी. राज्य 1994 (5) पूरक एससीआर 368 : (1995) 2 एससीसी 23; मीनू कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2006 (3) एससीआर 1086 : (2006) 4 एससीसी 359 ; किशन सिंह बनाम बिहार राज्य 1993 (1) एससीआर 31: (1993) 2 एससीसी 16; हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य। 2014 (2) एससीआर 1: (2014) 3 एससीसी 92; अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य 2012 (8) एससीआर 970: (2012) 12 एससीसी 406 - पर भरोसा किया।

कानून संदर्भ लिया गया

(2014) 3 एस. सी. सी. 306	आधार लिया गया।	पैरा 2
1994 (5) पूरक एससीआर 368	पर भरोसा किया।	पैरा 6
2006 (3) एससीआर 1086	पर भरोसा किया।	पैरा 8
1993 (1) एससीआर 31	पर भरोसा किया।	पैरा 13
2014(2) एससीआर 1	पर भरोसा किया।	पैरा 19
2012 (8) एससीआर 970	पर भरोसा किया।	पैरा 20

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के एस. बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1591 /2015 के 18.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थियों के लिए राजू रामचंद्रन वरिष्ठ अधिवक्ता, उसके साथ नीरज कुमार, विजय कुमार थलन, विक्रम आदित्य नारायण, अधिवक्ता

प्रत्यर्थिगण के लिए डॉ. सुशील बलवाड़ा, जय नादना, के. सिंह माने, अनीश माहेश्वरी, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, न्यायाधिपति

1. इस अपील में अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह के माता-पिता हैं, जिनकी शादी 24.02.2014 को रेनू से हुई थी। 27.11.2014 को यानी शादी के दस महीने के भीतर ही रेनू मृत पाई गई। मौत का कारण फांसी के कारण दम घुटना बताया गया। यहां प्रत्यर्थी नंबर 2 (मृतका के पिता) द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों की दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण रेनू को उसके पति अभिमन्यु सिंह और उसके माता-पिता (यहां अपीलार्थी) ने मार डाला था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 498-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अपीलार्थीओं ने दावा किया कि यह रेनू द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला था। जिस मामले की जांच की गई परिणामस्वरूप केवल अभिमन्यु के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, वह भी आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए, अर्थात्, रेनू द्वारा की गई आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए। पुलिस जांच के अनुसार दहेज की मांग की गई और धारा 498-ए और 304-बी आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इसके बजाय यह आत्महत्या का मामला था और अधिक से

अधिक अभिमन्यु पर रेनू द्वारा की गई आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया जा सकता था । इस कारण से, यहां अपीलार्थीओं के खिलाफ कोई चालान दायर नहीं किया गया था। दिनांक 24.02.2015 को पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रत्यर्थी नंबर 2 ने धारा 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत अपीलार्थियों और अभिमन्यु के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, (जेएमएफसी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन को विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11.03.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष कमिट किया क्योंकि धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सेशन कोर्ट के समक्ष, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक बार फिर इसी तरह का आवेदन प्रस्तुत किया। यहां, प्रत्यर्थी नंबर 2 अपने प्रयास में सफल रहा जैसा कि दिनांक 08.10.2015 के आदेश के तहत है, विद्वान सत्र न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304-बी और 498-ए और वैकल्पिक रूप से, धारा 306 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी और उनका बेटे के विरुद्ध संज्ञान लिया। । इस प्रकार, उन्होंने अपीलार्थीओं के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।

2. उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीओं ने अपने बेटे अभिमन्यु के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.11.2015 के तहत मामले को धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्न((2014) 3 एससीसी 306) मामलों में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में पक्षों को सुनने और आगे के आदेश पारित करने के निर्देश के साथ वापस सत्र न्यायालय में भेज दिया। सत्र न्यायालय ने नए सिरे से सुनवाई की और उसके बाद दिनांक 08.12.2015 को आदेश पारित किया, जिससे आवेदन को एक बार फिर धारा 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत संज्ञान लेने की अनुमति दी गई और वैकल्पिक रूप से,

अपीलार्थिगण एवं उनके बेटे के खिलाफ धारा 306 आईपीसी के तहत भी संज्ञान लिया गया। अपीलार्थिगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने 18.12.2015 को खारिज कर दिया है। यह आदेश वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित किया गया है।

3. हम शुरुआत में यह दर्ज कर सकते हैं कि एकमात्र आधार जिस पर आदेश को उच्च न्यायालय के साथ-साथ हमारे समक्ष चुनौती दी गई थी, वह यह है कि जब मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11.03.2015 के आदेश के तहत शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था और आईपीसी की धारा 304-बी और 498-ए के तहत संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। और यह आदेश अंतिम रूप ले चुका था क्योंकि शिकायतकर्ता या लोक अभियोजक द्वारा कोई पुनरीक्षण याचिका/आपराधिक विविध अपील नहीं की गई थी, उसी राहत के साथ दूसरा आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए पोषणीय नहीं था। यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि यह सत्र न्यायालय द्वारा दूसरी बार संज्ञान लेने जैसा है जो कानून में अनुमति योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'संहिता') की धारा 190 के तहत, अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है।

4. इस प्रकार, हमारे सामने यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या सत्र न्यायालय को आईपीसी की धारा 304-बी और 498-ए के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार था, जब इस आशय का एक समान आवेदन जेएमएफसी(जूडिशल मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास) द्वारा मामले को सत्र न्यायालय में कमिट करते समय खारिज कर दिया गया था, केवल धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान ले कर और विशेष रूप से धारा 304-बी और 498-ए आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए।

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया कि जब मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट कमिट करने की कार्यवाही पूरी करने के बाद मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सौंप सकता है। वह पुलिस रिपोर्ट से यह पता चलने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामले को कमिट कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज सकता है। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान न लेकर पूर्व दृष्टिकोण अपनाता है और सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए मामला कमिट करता है, सत्र न्यायालय संहिता की धारा 193 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और धरम पाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। तथापि, यदि मजिस्ट्रेट वैकल्पिक कार्यवाही अपनाता है, अर्थात्, अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, तो सत्र न्यायालय को अपराध का नए सिरे से संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि अपराध का संज्ञान केवल एक बार किया जा सकता है। पुनः, इस प्रस्ताव के समर्थन में, धरम पाल के मामले में निर्णय की सहायता ली जाती है।

6. इसके विपरीत, डॉ. सुशील बलवाड़ा, विद्वान वकील जो प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश हुए और श्री अनीश माहेश्वरी, विद्वान वकील जो राज्य की ओर से पेश हुए तर्क दिया कि चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, इसलिए यह केवल सत्र न्यायालय है जो संज्ञान लेने के लिए सक्षम है और इसलिए, सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 संहिता की धारा 193 के संदर्भ में पहली बार अपराध का संज्ञान लेते हुए माना जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, प्रत्यर्थीगण भी धरम पाल का मामले के निर्णय पर भरोसा करते हैं। इसके

अलावा, उन्होंने निसार और अन्य बनाम यू. पी. राज्य(1995 2 SCC 23) में इस न्यायालय के फैसले पर भी आश्रय लिया। :

7. उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों पक्ष धर्मपाल के ई मामले में फैसले से समर्थन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार, उक्त निर्णय में अनुपात पर उचित ध्यान देना होगा। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, हम संहिता की धारा 190 और 193 के प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे जो वर्तमान मामले में लागू हुए हैं क्योंकि हमारी राय में, उनकी उचित समझ, मौजूदा मुद्दे का स्पष्ट उत्तर प्रदान करेगी और हमें उस मामले में निर्धारित अंतर्निहित कानूनी सिद्धांत का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह प्रावधान निम्नलिखित हैं:

“190. मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान

1. इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, कोई भी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और उपधारा (2) के तहत विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है-

(ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं;

(बी) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर

(सी) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर अधिकारी, या अपने स्वयं के ज्ञान पर, कि इस तरह का अपराध किया गया है प्रतिबद्ध।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिकार दे सकता है। की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेने के लिए द्वितीय श्रेणी का ऐसे अपराध जो जाँच करने की उसकी क्षमता के भीतर हों।

XX

XX

XX

193. सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान। - सिवाय इसके कि तत्काल प्रभाव से, मूल अधिकारिता के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी सत्र न्यायालय नहीं लेगा जब तक कि मामला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसके अधीन नहीं किया गया हो"।

8. संहिता की धारा 190 और 193 अध्याय XIV में हैं। इस अध्याय में "कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें" शीर्षक शामिल है। धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध के संज्ञान से संबंधित है। यह प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाता है, जो इसमें उल्लिखित तीन परिस्थितियों के तहत "किसी भी अपराध" का संज्ञान लेने के लिए विशेष रूप से सशक्त हैं। इन तीन परिस्थितियों में पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेना शामिल है ऐसे तथ्यों की जो अपराध बनाते हैं। यह साधारण कानून है कि जब पुलिस रिपोर्ट यह कहते हुए दायर की जाती है कि कोई अपराध नहीं बनता है, तब भी मजिस्ट्रेट जांच द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को नजरअंदाज कर सकता है। अधिकारी जांच से सामने आने वाले तथ्यों पर अपना स्वतंत्र दिमाग लगाने और मामले का संज्ञान लेने में सक्षम है यदि उसे लगता है कि जांच से सामने आने वाले तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि अपराध हुआ है। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(ए) के तहत मामले का संज्ञान लेने के लिए संहिता की धारा 200 और 202 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि धारा 200 या धारा 202 के तहत कार्य करना उसके लिए विकल्प है। {मीनू कुमारी और अन्य बनाम बिहार का राज्य और अन्य((2006) 4

एससीसी 359)देखें।} इस प्रकार, जब अधिनियम की धारा 190(1)(a) के तहत मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 200 या 202 में निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेने और फिर संज्ञान लेने का अधिकार है। यदि पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो वह ऐसी रिपोर्ट पर संज्ञान लेगी, जैसा कि ऊपर उल्लिखित तरीके से संहिता की धारा 190(1)(बी) के तहत प्रदान किया गया है जैसा कि मीनू कुमारी के मामले में उजागर किया गया है।

9. इसी तरह, संहिता की धारा 193 सत्र न्यायालय को अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देती है और कहती है कि सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पास कमिट नहीं किया गया हो इस संहिता के तहत। इस धारा के अनुसार, सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे जाने के बाद ही संज्ञान ले सकता है। हालाँकि, एक बार जब मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंप दिया जाता है, तो सत्र न्यायालय को 'मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए संज्ञान लेने का अधिकार होता है।

10. उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए प्रश्न यह उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकता है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है या उसे मुकदमा चलाने की कार्यवाही पूरी होने के बाद मामले को केवल सत्र न्यायालय को सौंपना है क्योंकि सत्र न्यायालय ही इस तरह के मामले के विचारण के लिए सक्षम है। एक ओर, संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेट को "किसी भी अपराध का संज्ञान लेने" का अधिकार देती है, जिससे यह आभास होता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट उस अपराध का भी संज्ञान लेते हैं जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दूसरी ओर, जब मामला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है, तो संहिता की धारा 193 यह निर्धारित करती है कि सत्र न्यायालय 'मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में' संज्ञान लेगा, जो दर्शाता है

कि संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया है। सत्र न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के रूप में और, इस प्रकार, यह पहली बार है कि संज्ञान लिया गया है और मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कोई भी आदेश उस अपराध का संज्ञान लेने के समान नहीं है जो विचारणीय है। सत्र न्यायालय।

11. संहिता की धारा 190 का एक संक्षिप्त अध्ययन जो इसका उपयोग करता है अभिव्यक्ति "कोई भी अपराध" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है मजिस्ट्रेट कि मजिस्ट्रेट केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध के लिए संज्ञान ले सकता है, न कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध के संबंध में। इस प्रकार, उसके पास उस अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यदि ऐसा है, तो सवाल यह है कि जब सत्र न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो संहिता की धारा 193 में आने वाले " मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में" शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाए। अन्यथा कहें तो, जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है और उसके बाद केवल मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया है , तो क्या सत्र न्यायालय को संहिता की धारा 193 के तहत किसी अपराध का फिर से संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है या उसके पास अभी भी संज्ञान लेने की शक्ति है, मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए। जवाब खोजने के लिए, अब हम धर्मपाल के मामले का मूल्यांकन के लिए बढ़ते हैं।

12. धरम पाल के मामले में, एक एन और अपीलार्थियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 323 सपठित धारा 34 के तहत अपराध करने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 173(2) के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रिपोर्ट के कॉलम 2 में अपीलार्थीगण के नाम शामिल करते हुए केवल एन को सुनवाई के लिए भेजा गया। ऐसी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर , मजिस्ट्रेट ने सीधे मामले को सत्र न्यायालय में नहीं

भेजा, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, अपीलार्थीगण को अन्य आरोपी एन के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया क्योंकि मजिस्ट्रेट आश्वस्त थे कि अपीलार्थीगण के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने का मामला बनता है। इसके अलावा, ऐसा करते समय, मजिस्ट्रेट ने कोई और पूछताछ नहीं की, जैसा कि संहिता की धारा 190, 200 या यहां तक कि 202 के तहत विचार किया गया था, लेकिन केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सम्मन जारी करने के लिए आगे बढ़े। इस पृष्ठभूमि में संविधान पीठ के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचार हेतु उठे:

"7.1 क्या पुलिस की रिपोर्ट से यह पता चलने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, सत्र न्यायालय को मामला सौंपने के बाद कमिटिंग मजिस्ट्रेट की कोई अन्य भूमिका है?

7.2 यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है और आश्वस्त है कि रिपोर्ट के कॉलम 2 में रखे गए व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का मामला बनाया गया है, तो क्या उसके पास उनके खिलाफ भी समन जारी करने का क्षेत्राधिकार है, पुलिस रिपोर्ट में दर्ज मामले के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए नफे सिंह के साथ उनके नाम भी शामिल करने का ?

7.3 अपीलार्थियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्णय लेने के बाद, क्या मजिस्ट्रेट को शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन करना था और मुकदमा चलाने के लिए उन्हें सत्र न्यायालय में भेजने से पहले साक्ष्य लेना था या क्या उनका पालन किए बिना उनके खिलाफ समन जारी करना उचित प्रक्रिया थी?

7.4 क्या सत्र न्यायाधीश मूल क्षेत्राधिकार वाली अदालत के रूप में सीआरपीसी की धारा 193 के तहत समन जारी कर सकते हैं?

7.5 मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने पर, क्या सत्र न्यायाधीश संहिता की धारा 193 के तहत अलग से समन जारी कर सकता है या क्या उसे इसका सहारा लेने के लिए संहिता की धारा 319 के तहत चरण तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा?

7.6 रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य ((1998) 7 एससीसी 149), जिसने किशन सिंह बनाम बिहार राज्य ((1993) 2 SCC 16),में निर्णय को दरकिनार कर दिया। सही निर्णय लिया या नहीं? "

संदर्भ का जवाब देते हुए संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:

(ए) मजिस्ट्रेट के पास अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने की पर्याप्त शक्तियां हैं जो पुलिस अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 173(2) के तहत दायर की जा सकती हैं और पुलिस रिपोर्ट से परे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति है। संहिता की धारा 173(2) के तहत उसके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मजिस्ट्रेट की भूमिका होती है। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है, तो उसके पास दो विकल्प हैं। वह दायर की जा सकने वाली विरोध याचिका के आधार पर कार्रवाई कर सकता है, या वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए भी प्रक्रिया जारी कर सकता है और आरोपी को तलब कर सकता है। इसके बाद यदि प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाएं कि मामला बन गया है तो आगे बढ़ें रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों के खिलाफ, वह उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है या यदि वह संतुष्ट है कि एक मामला बनाया गया था जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, तो उसे मामले में आगे बढ़ने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को

सौंपना होगा। इसके अलावा, यदि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो उसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा और या तो मामले की जांच करनी होगी या यदि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाया जाता है तो इसे सत्र न्यायालय को सौंपना होगा।

(बी) सत्र न्यायाधीश संहिता की धारा 193 के तहत समन जारी करने का हकदार है मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सौंपे जाने पर धारा 193 सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान की बात करती है। अनुभाग में मुख्य शब्द यह हैं कि कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि इस संहिता के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सौंपा न गया हो।' धारा 193 के प्रावधान में कहा गया है कि किसी मामले को सबसे पहले, मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए । दूसरी शर्त यह है कि मामला सौंपे जाने के बाद ही सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपराध का संज्ञान ले सकता है। यह प्रस्तुत करना कि धारा 193 में दर्शाया गया संज्ञान किसी अपराध के संज्ञान से नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कमित करने के आदेश से संबंधित है, धारा 193 के स्पष्ट शब्दों के मद्देनजर विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था कि सत्र न्यायालय इसके उक्त अनुभागों के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकता है।

(सी) किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, अपराध का नए सिरे से संज्ञान लेने और उसके बाद, समन जारी करने की कार्यवाही करने का सवाल, कानून के अनुसार नहीं है। यदि अपराध का संज्ञान लिया जाना है, तो इसे मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। संहिता की धारा 193 की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र

न्यायालय में भेजे जाने के बाद, सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार मान लेता है और वह सब कुछ ऐसे क्षेत्राधिकार की धारणा के साथ चलता है। इसलिए, संहिता की धारा 209 के प्रावधानों को यह समझना होगा कि पुलिस रिपोर्ट से यह पता चलने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था , मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने (कमिट करने) में निष्क्रिय भूमिका निभा रहा है। आंशिक संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने और आंशिक संज्ञान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता।

13. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने किशुन सिंह के मामले में व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार कर लिया कि सत्र न्यायालय के पास किसी मामले के कमिट हो कर आने पर, क्षेत्राधिकार होता है, कि वह उस व्यक्ति के अपराधों का संज्ञान ले सके जिसे अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया है लेकिन मामले में जिसकी संलिप्तता रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट होती हो। यह विशेष रूप से माना गया कि संहिता की धारा 209 के तहत, मामला कमिट होने पर, सत्र न्यायाधीश पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में दिखाए गए लोगों को पहले से ही नामित लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुला सकता है।

14. दिलचस्प बात यह है कि साथ ही, न्यायालय ने यह भी माना कि यह मानना सही नहीं होगा कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर और यह देखते हुए कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट के पास कमिट करने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाती है और सत्र न्यायाधीश को उन व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले संहिता की धारा 319 के तहत चरण तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ता है, जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जो मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मामले के कागजात में निहित सामग्री से बनता है। । यह निम्नलिखित परिच्छेद में परिलक्षित होता है:

"33. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, हम श्री चाहर और श्री दवे द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह देखते हुए कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट के पास कोई अन्य कार्य नहीं है, मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को कमिट करने के अलावा, जो किसी अन्य व्यक्ति को मुकदमे में आरोपी के रूप में पेश करने के लिए केवल संहिता की धारा 319 का सहारा ले सकता है। दूसरे शब्दों में, श्री दवे के अनुसार, संहिता की धारा 190(1)(बी) और धारा 204 के तहत आरोपी को समन जारी करने के बीच कोई मध्यस्थ चरण नहीं हो सकता है। इस तरह की व्याख्या के प्रभाव से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां न तो कमिटिंग मजिस्ट्रेट का पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण होगा और न ही सत्र न्यायाधीश का, जब तक कि मुकदमे में धारा 319 के चरण तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा, यदि सत्र न्यायाधीश को पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों के खिलाफ सामग्री मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करना होगा, जिससे न केवल मुकदमे की पुनरावृत्ति होगी, बल्कि यह लम्बा भी खिंच जाएगा।"

हालाँकि, जब हम चर्चा को समग्रता में देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उपरोक्त टिप्पणियाँ संविधान पीठ द्वारा पैरा 7.1 में उठाए गए पहले प्रश्न के संबंध में की गई थीं, जो पहले से ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट की शक्तियां सत्र न्यायालय में मामले को कमिट करने पर, इसका उत्तर दिया जाना था। यह निर्णय के अगले ही पैरा, यानी पैरा 34 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें किशुन सिंह के मामले में निर्धारित आदेश को मंजूरी देते हुए, संविधान पीठ ने माना कि मजिस्ट्रेट के पास

अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने की पर्याप्त शक्तियां हैं। के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर किया गया संहिता की धारा 173(2) और पुलिस रिपोर्ट से परे जाकर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति है, जो शक्ति धारा 319 चरण तक पहुंचने तक सत्र न्यायालय के पास नहीं है।' फैसले के पैरा 35 में इसे किसी भी विवाद से परे रखा गया था, जो इस प्रकार है:

" 35. हमारे विचार में, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत उसके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने पर मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मजिस्ट्रेट की एक भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत होता है, उसके पास दो विकल्प होते हैं। वह दायर की जा सकने वाली नाराजगी याचिका के आधार पर कार्रवाई कर सकता है, या वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए भी प्रक्रिया जारी कर सकता है और आरोपी को तलब कर सकता है। इसके बाद, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि कोई मामला बनता है रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, तो उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ें या यदि वह संतुष्ट है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वह मामले में आगे बढ़ने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप (कमिट कर) सकता है।"

15. इस स्तर इस चरण तक की चर्चा इस सिद्धांत को निर्धारित करके मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उत्तर देती है कि भले ही मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, मजिस्ट्रेट का कार्य केवल एक डाकघर के रूप में कार्य करना और मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना (कमिट करना) नहीं है, लेकिन उसे संज्ञान लेने, प्रक्रिया जारी करने और आरोपी को बुलाने और उसके बाद मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने

का भी अधिकार है । इसके संबंध में स्थिति एक बार स्पष्ट हो जाएगी जब हमें संविधान पीठ द्वारा ऊपर दिए गए पैरा 7.4 से 7.6 के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हम इस संबंध में उक्त निर्णय के पैरा 37 से 41 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, इस संबंध में उक्त निर्णय जो इस प्रकार है:

"37. प्रश्न 4, 5 और 6 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रश्न 4 का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, अर्थात्, सत्र न्यायाधीश को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे जाने पर सीआरपीसी की धारा 193 के तहत समन जारी करने का अधिकार है।

38. संहिता की धारा 193 सत्र न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान की बात करती है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:

"193. सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान - इस संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सेशन न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि मामला न हो। इस संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए प्रतिबद्ध किया गया है।"

अनुभाग में मुख्य शब्द यह हैं कि "कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि इस संहिता के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सौंपा (कमिट किया) न गया हो"। उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि एक मामला, सबसे पहले, मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मामला सौंपे

जाने के बाद ही सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपराध का संज्ञान ले सकता है। हालाँकि, श्री दवे द्वारा यह सुझाव देने का प्रयास किया गया है कि धारा 193 में दर्शाया गया संज्ञान किसी अपराध के संज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रतिबद्धता आदेश से संबंधित है, हम स्पष्ट रूप से इस तरह के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। धारा 193 के शब्दों में कहा गया है कि सत्र न्यायालय उक्त धारा के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकता है।

39. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या धारा 209 के तहत, मजिस्ट्रेट को मामले को सत्र न्यायालय में भेजने से पहले अपराध का संज्ञान लेना आवश्यक था। यह सर्वविदित है कि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार ही लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, अपराध का नए सिरे से संज्ञान लेने और उसके बाद, समन जारी करने का सवाल कानून के अनुसार नहीं है। यदि अपराध का संज्ञान लेना है, तो इसे सत्र न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। संहिता की धारा 193 की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक बार जब मामला विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है, तो सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार मान लेता है और यह सब ऐसे क्षेत्राधिकार की धारणा के साथ चलता है। इसलिए, धारा 209 के प्रावधानों को यह समझना होगा कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट से यह पता लगाने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामले को

सत्र न्यायालय में सौंपने में निष्क्रिय भूमिका निभाई । न ही आंशिक संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने और आंशिक संज्ञान विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए जाने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

40. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमें किशुन सिंह मामले में व्यक्त विचारों से सहमत होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सत्र न्यायालय के पास किसी मामले को सौंपने का अधिकार क्षेत्र है, ताकि अपराधियों के रूप में नामित नहीं किए गए व्यक्तियों के अपराधों का संज्ञान लिया जा सके, लेकिन मामले में जिनकी मिलीभगत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट होगी। इसलिए, साक्ष्य दर्ज किए बिना भी, धारा 209 के तहत मामला कमिट होने पर, सत्र न्यायाधीश पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में दिखाए गए लोगों को पहले से ही नामित लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाते हैं।

41. हम श्री दवे की इस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि सत्र न्यायालय के पास उन व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले धारा 319 सीआरपीसी के तहत चरण तक पहुंचने तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिनके खिलाफ सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए मामले के कागजात में निहित है।"

16. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पैरा 7.4 में प्रश्न था सत्र न्यायाधीश ने विशेष रूप से सकारात्मक धारणा में उत्तर दिया कि 'मूल क्षेत्राधिकार का' एक न्यायालय के रूप में संहिता की धारा 193 के तहत समन जारी करने का हकदार है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था और उसके बाद ही मामले को सत्र

न्यायालय को सौंप दिया था, जैसा कि पहले से ही ऊपर उल्लेखित उक्त मामले के तथ्यों से स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून में अन्य स्थापित स्थिति के विपरीत है, अर्थात्, किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है और उस स्थिति में मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय को कमिट कर देता है। उसके बाद अपराध का पहले संज्ञान लेने का प्रश्न कानून के अनुरूप नहीं होगा। इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास को हल करने के लिए, न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया कि संहिता की धारा 209 के प्रावधानों को यह समझना होगा कि मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय में भेजने में निष्क्रिय भूमिका निभाता है। पुलिस की रिपोर्ट है कि मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय था।

17. जैसा कि ऊपर बताया गया है, संविधान पीठ इस फैसले में किशुन सिंह के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत है। उस फैसले में न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित तरीके से समझाया और स्पष्ट किया था:

"16. . हम पहले ही रघुबंस दुबे, (1967) 2 एससीआर 423, और हरेराम, (1978) 4 एससीसी 58 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात से संकेत दे चुके हैं कि एक बार, अदालत अपराध का संज्ञान ले लेती है (अपराधी नहीं) वास्तविक अपराधियों का पता लगाना अदालत का कर्तव्य बन जाता है और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि पुलिस द्वारा मुकदमे के लिए रखे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य लोग भी अपराध में शामिल थे, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह उन्हें पहले से नामित लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाएं , क्योंकि उन्हें बुलाना केवल संज्ञान लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा। हमने दोनों संहिताओं की धारा 193 की भाषा में अंतर भी बताया है; पुरानी संहिता के तहत न्यायालय सेशन

को मूल क्षेत्राधिकार की अदालत के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से तब तक रोक दिया गया था जब तक कि आरोपी इसके लिए प्रतिबद्ध(कमिटेड) नहीं था, जबकि वर्तमान संहिता के तहत आरोपी शब्द के स्थान पर केस शब्द का उपयोग करके प्रतिबंध को कमजोर कर दिया गया है। इस प्रकार, धारा 193 को पढ़ते हुए, जैसा कि यह वर्तमान में मौजूद है, एक बार जब मामला संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है, तो किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सत्र न्यायालय की शक्ति पर मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत के रूप में प्रतिबंध हट जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय में भेजने पर रोक लगाई जाती है धारा 193 को हटा दिया गया है, जिससे सत्र न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने के लिए मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का पूर्ण और निर्बाध क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गया है, जिसमें उस व्यक्ति या व्यक्तियों को बुलाना शामिल होगा जिनकी अपराध के कमीशन में संलिप्तता प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री में देखी जा सकती है। .."

18. एक और मामला, जिसने किशुन सिंह के मामले में उपरोक्त कानूनी स्थिति को दोहराया, निसार और अन्य बनाम यू. पी. राज्य ((1995) 2 SCC 23) व अन्य है।

19. जहां तक निर्णय की बात है, तो हरदिप सिंह बनाम. पंजाब राज्य और **Ors.**((2014)3SCC 92) मामले का संबंध है, जो कि संहिता की धारा 319 में निहित ट्रायल कोर्ट की शक्तियों से संबंधित है, जो ट्रायल कोर्ट को उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का अधिकार देता है, जिन्हें आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। उक्त मामले में संविधान पीठ ने मुख्य रूप से उस चरण के मुद्दे पर विचार किया

जिस पर संहिता की धारा 319 के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना है और संबंधित मुद्दे कि 'सबूत' शब्द का अर्थ क्या है। संहिता की धारा 319(1) में उपयोग किया जाता है जिसके आधार पर उन लोगों को समन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जिन्हें पहले आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। इसलिए, उस फैसले पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी नहीं है क्योंकि जिस सवाल से हम चिंतित हैं उसका जवाब संविधान पीठ ने धर्मपाल के मामले में अपने फैसले में ही दे दिया है, जिस से हम बाध्य हैं। इस निर्णय के अनुसार, चूँकि सत्र न्यायालय संहिता की धारा 193 के तहत मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही सौंपे जाने के बाद, उसे संज्ञान लेने और सम्मन जारी करने का अधिकार है और इसे उसी अपराध का दोबारा संज्ञान लेना नहीं माना जाएगा।

20. अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य ((2012 12 SCC 406) में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले से यह दृष्टिकोण और मजबूत हो जाता है। उस मामले में, न्यायालय ने माना कि जब अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट को मामले को सत्र न्यायालय को कमित करना चाहिए और अपराध का संज्ञान लेने से इनकार नहीं कर सकता और पहले प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर आरोपी को बरी नहीं कर सकता। उक्त निर्णय में निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा

"14. इस न्यायालय ने मजिस्ट्रेट की क्षमता के बारे में, संजय गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडियो, (1978) 2 एससीसी 39 में, एक आरोपी को आरोप मुक्त कर देने जैसे तत्काल मामले में है, यह कहा गया:

"3 प्रतिबद्ध (कमिटेड) न्यायालय के लिए यह स्वयं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करना खुला विकल्प नहीं है कि प्रथम दृष्टया मामला गुण-दोष के आधार पर बनाया गया है। अधिकार क्षेत्र एक बार

पहले के कोड के तहत उसे निहित था लेकिन अब वर्तमान संहिता के तहत समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, यह मानना कि प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए भी वह योग्यता में जा सकता है, धारा 207-ए (पुरानी संहिता) को उसके वर्तमान गैर-विवेकाधीन आकार में फिर से ढालने में संसद के उद्देश्य को विफल करता है। उद्देश्य जल्दी निस्तारण था परिवर्तन और यह सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा यदि व्याख्यात्मक रूप से हम मानते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे का ड्रेस रिहर्सल क्रम में है। हमारे विचार में, वह संकीर्ण निरीक्षण छेद जिसके माध्यम से कमिटिंग मजिस्ट्रेट को मामले को देखना होता है, उसे केवल यह पता लगाने तक सीमित करता है कि क्या मामला, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट द्वारा खुलासा किया गया है, मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध दिखाता है। पुलिस रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को सही मानते हुए,... मजिस्ट्रेट को बस सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा कमिट करना है यदि, गलती से, दंड संहिता की कोई गलत धारा उद्धृत की जाती है, तो वह उस पहलू पर गौर कर सकता है... यदि किसी भी सामग्री द्वारा असमर्थित मनगढ़ंत तथ्य पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं और एक सत्र अपराध सामने लाया जाता है, तो यह है सीआरपीसी की धारा 227 के तहत सत्र न्यायालय अभियुक्त को आरोप मुक्त करने के लिए पूरी तरह से खुला है। यह प्रावधान आरोपी की कथित शिकायत का ख्याल रखता है।" (जोर दिया गया)

इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि जब कोई अपराध सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञेय होता है, तो मजिस्ट्रेट मामले की जांच नहीं कर

सकता और अभियुक्त को आरोपमुक्त नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद भी उसके लिए ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसके पास मामले की जांच करने या उसे देखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसकी चिंता यह देखने में होनी चाहिए कि दंडात्मक कानून के किन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और यदि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध का उल्लेख किया गया है, तो उसे मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए।

15. इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि मजिस्ट्रेट के पास अपीलार्थी को मुक्त करने का कोई काम नहीं था। दरअसल, पुरानी सीआरपीसी की धारा 207-ए, मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती थी। हालाँकि, सीआरपीसी, 1973 में, उक्त धारा 207-ए के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। वह कानून के तहत मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए बाध्य था, जहां आरोपमुक्त करने के लिए ऐसा आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसलिए, निर्वहन का आदेश एक शून्यता है, जो क्षेत्राधिकार के बिना है।

XX XX XX

17. जहां जांच एजेंसी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वहां न्यायालय को संज्ञान न लेने का रास्ता अपनाकर बरी करने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए। इससे भी अधिक, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह पीड़ित के अधिकारों और हितों की रक्षा करे, जो डिस्चार्ज कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। धारा 227 के आवेदन के चरण में, अदालत को यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों को छांटना

होगा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। इस प्रकार, इस स्तर पर साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है। (ज़रिए पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398, और आर.एस . मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य, (2011) 2 एससीसी 689)

18. संहिता की योजना, विशेष रूप से, सीआरपीसी की धारा 207 से 209 के प्रावधान, मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र दायर होने पर मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने का आदेश देते हैं। इन प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस द्वारा शुरू किए गए मामले में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले को कमिट करना अनिवार्य है। संहिता की योजना बस यह प्रदान करती है कि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित कर सकता है कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हैं या नहीं। एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि रिपोर्ट में कथित तथ्य विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध बनते हैं, तो उसे मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना होगा।

19. मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संज्ञान लेने से इनकार कर सकता है यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इसकी मांग करती है। ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि शिकायत, केस डायरी, धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज गवाहों के बयान, यदि कोई हो, तो कोई अपराध नहीं बनता है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करता

है । हालाँकि, वह रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना नहीं कर सकता है और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि कौन सा सबूत स्वीकार्य है, या उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, इस स्तर पर साक्ष्य की सराहना अस्वीकार्य है। मजिस्ट्रेट मामले में सबूतों और संभाव्यता के संतुलन को तौलने में सक्षम नहीं है।"

21. उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनके तहत सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया था। यहां एक मामला है जहां पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को सौंपी गई थी, आइ ओ ने अपीलार्थिगण को आरोपी व्यक्तियों के रूप में शामिल नहीं किया था। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थिगण के खिलाफ भी संज्ञान लेने की प्रार्थना के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया था। इस आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, इस मामले में स्थिति यह नहीं है कि संहिता की धारा 173(8) के तहत दायर जांच रिपोर्ट/आरोपपत्र में अपीलार्थिगण को फंसाया गया है और अपीलार्थिगण ने तर्क दिया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके विपरीत, पुलिस ने स्वयं अपनी अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि अपीलार्थिगण के खिलाफ मामला नहीं बनता था। शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई थी, जो चाहता था कि मजिस्ट्रेट इन अपीलार्थिगण को भी समन करे और इस उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता द्वारा संहिता की धारा 190 के तहत आवेदन दायर किया गया था। अपीलार्थिगण ने उक्त आवेदन का उत्तर दिया था और दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट का आदेश उचित सोच-समझकर पारित किया गया था, जिसके तहत उन्होंने अपीलार्थिगण के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और इसे केवल अपीलार्थिगण के बेटे तक ही सीमित रखा। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई। आम

तौर पर , ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय में सौंपते समय 'निष्क्रिय भूमिका' निभाई थी। इस प्रकार , उन्होंने उचित दिमाग लगाने और इस प्रक्रिया में "सक्रिय भूमिका" निभाने के बाद संज्ञान लिया था। स्थिति अलग होती यदि मजिस्ट्रेट ने मामले को कमिट करते समय शिकायतकर्ता के आवेदन को सीधे सत्र न्यायालय में कमिट कर दिया होता। इस परिदृश्य में, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है। इसके बावजूद, सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष दिए गए इसी तरह के आवेदन पर संज्ञान लिया। आम तौर पर, ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी।

22. अगला प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय ऐसे आदेश पर रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। हमने पाया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश पुनरीक्षण योग्य है। पुनरीक्षण की इस शक्ति का प्रयोग वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जो इस मामले में, स्वयं सत्र न्यायालय होगा, या तो पुनरीक्षण याचिका पर जो पीड़ित पक्ष द्वारा दायर की जा सकती है या यहां तक कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है । इस प्रकार, सत्र न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में आदेश पारित करने के लिए शक्तिहीन नहीं था। अगर वह आक्षेपित आदेश अपीलकर्ताओं को कोई अवसर दिए बिना उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेता तो चीजें अलग होतीं, क्योंकि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के साथ इन अपीलार्थिगण के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार अर्जित हुआ था। हालाँकि, मौजूदा मामले में, हम पाते हैं कि यहां अपीलार्थिगण को उचित अवसर दिया गया था जिन्होंने शिकायतकर्ता के आवेदन का जवाब पेश किया था और सत्र न्यायालय ने भी उनकी दलीलें सुनी थीं। इस कारण से, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने इच्छुक नहीं हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।